>

Title : Need to monitor the progress of various welfare schemes meant for Scheduled Tribes and Adivasis being implemented in Bharuch Parliamentary Constituency, Gujarat and other parts of the country, with a view to bring them in the national mainstream.

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच): देश में अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अनेक योजनाएं चल रही हैं एवं इन योजनाओं में करोड़ों रूपया खर्च हो रहा है। परन्तु, अनुसूचित जनजाति के कल्याण एवं उनके विकास करने के लिए जो धनराशि आबंटित एवं खर्च हो रही है वह अनुसूचित जनजाति तक नहीं पहुंच रही है। स्थानीय सांसदों को यहां तक पता नहीं लग पाता है कि उनके क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए कितना पैसा आया और कितना खर्च हुआ। इसकी निगरानी व्यवस्था में केन्द्र सरकार ने स्थानीय सांसदों को कोई भूमिका नहीं दे रखी है। मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच एवं नर्मदा जिलों में अनुसूचित जनजाति बहुसंख्या में रहते हैं, पर वहां पर यह योजना प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रही है। केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति को वन भूमि पर स्वामित्व का अधिकार एवं उनके विकास के लिए अनेक कानून बनाए हुए हैं, उनका लाभ भी अनुसूचित जनजाति को नहीं मिल पा रहा है।

सदन के माध्यम से अनुरोध है कि अनुसूचित जनजाति के कल्याण एवं विकास योजनाओं के कार्यों की समीक्षा की जाये और इसमें पाये गये दोषों को दूर करके वनों में रहने वाले आदिवासियों का विकास कर उनको राष्ट्रीय धारा में लाया जाये।